International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में ऑनलाइन शिक्षा नीति की भूमिका: सीकर जिले का अध्ययन

रोहित गिठाला
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
पंजी. नं. JVR-II/23/12303

डॉ. दिनेश कुमार वर्मा
शोध–निर्देशक, कानून और प्रबंधन संकाय के अंतर्गत, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश
प्रस्तुत शोधपत्र राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में ऑनलाइन शिक्षा नीति की भूमिका का विश्लेषण करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग माना है तथा पीएम ई–विद्या, दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसी पहलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। कोविड–19 महामारी के बाद राजस्थान सरकार ने भी 'स्माइल' और 'ई–कक्षा' जैसे कार्यक्रमों द्वारा विद्यालयी शिक्षा को डिजिटल माध्यम से जोड़ा। सीकर जिला एक ओर कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, तो दूसरी ओर इसके ग्रामीण अंचलों में डिजिटल संसाधनों, इंटरनेट संपर्क और डिजिटल साक्षरता की असमानता अब भी विद्यमान है।
यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें सरकारी नीतिगत दस्तावेजों, जनगणना, यू–डाइस प्लस, असर रिपोर्ट तथा संबंधित शोध–साहित्य जैसे द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन शिक्षा नीति ने ग्रामीण युवाओं को अध्ययन सामग्री तक सुलभ पहुँच, कम खर्च में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा के लचीले अवसर प्रदान किए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण बालिकाओं के लिए घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने की संभावना बढ़ी है। फिर भी स्मार्टफोन की सीमित उपलब्धता, कमजोर नेटवर्क, बिजली की अनियमितता, लैंगिक डिजिटल अंतर, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और स्थानीय भाषा में सामग्री की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। शोधपत्र निष्कर्ष निकालता है कि ऑनलाइन शिक्षा नीति तभी वास्तविक सशक्तिकरण का साधन बन सकती है जब डिजिटल अवसंरचना, सामुदायिक डिजिटल केंद्रों और मिश्रित शिक्षण मॉडल को ग्रामीण संदर्भ के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए।

मुख्य शब्द: ऑनलाइन शिक्षा नीति, ग्रामीण युवा, शैक्षिक सशक्तिकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल विभाजन

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की आधारशिला है। अमर्त्य सेन ने विकास को 'स्वतंत्रता के विस्तार' के रूप में परिभाषित करते हुए शिक्षा को वह क्षमता माना है जो व्यक्ति को अपने जीवन के विकल्प चुनने योग्य बनाती है। इसी दृष्टि से शैक्षिक सशक्तिकरण का अर्थ केवल साक्षरता या उपाधि प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का विकास है, जिससे युवा अपने जीवन और समुदाय की दिशा तय कर सके। पाउलो फ्रेरे भी शिक्षा को चेतना–जागरण की प्रक्रिया मानते हैं, जिसके द्वारा वंचित वर्ग अपनी परिस्थितियों को समझकर उन्हें बदलने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। भारत की लगभग दो–तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और देश की युवा आबादी का बड़ा भाग भी गाँवों में ही रहता है। ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालयों, विषय–विशेषज्ञ शिक्षकों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन से वंचित रहना पड़ा है। शहरों में जाकर पढ़ाई करना आर्थिक रूप से महँगा है और सामाजिक कारणों से, विशेषकर बालिकाओं के लिए, कई बार संभव भी नहीं होता। ऐसे में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित ऑनलाइन शिक्षा ने भौगोलिक दूरी और संसाधनों की कमी को पाटने की नई संभावना प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस संभावना को नीतिगत रूप दिया। नीति के अध्याय 23 और 24 में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसी दौरान कोविड–19 महामारी ने विद्यालयों और महाविद्यालयों को लंबे समय तक बंद रखने को विवश किया, जिससे ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प से आगे बढ़कर आवश्यकता बन गई। केंद्र सरकार ने पीएम ई–विद्या कार्यक्रम आरंभ किया और राजस्थान सरकार ने व्हाट्सऐप समूहों के माध्यम से 'स्माइल' कार्यक्रम तथा दूरदर्शन व यूट्यूब के माध्यम से 'ई–कक्षा' जैसी पहलें कीं। राजस्थान का सीकर जिला इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। शेखावाटी अंचल का यह जिला पिछले लगभग दो दशकों में चिकित्सा और अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है, जहाँ आसपास के गाँवों और अन्य जिलों से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। साथ ही जिले की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण है और जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता से काफी पीछे रही है। इस प्रकार सीकर में शिक्षा के प्रति गहरी आकांक्षा और संसाधनों की असमानता, दोनों साथ–साथ दिखाई देती हैं।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा नीति का स्वरूप और प्रमुख पहलें

भारत में ऑनलाइन शिक्षा की नीति किसी एक दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया अभियान और विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं का संयुक्त ढाँचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा तक पहुँच, समानता और गुणवत्ता तीनों में सुधार ला सकती है, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि डिजिटल विभाजन को दूर किए बिना ऑनलाइन शिक्षा

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

असमानता को बढ़ा भी सकती है। इसी कारण नीति में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) के गठन, ऑनलाइन शिक्षा के पायलट अध्ययनों, डिजिटल अवसंरचना के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर 'दीक्षा' (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) एक राष्ट्रीय मंच है, जहाँ पाठ्यपुस्तकों से जुड़ी क्यूआर कोड युक्त ई–सामग्री, वीडियो पाठ और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। मई 2020 में घोषित पीएम ई–विद्या कार्यक्रम ने दीक्षा, स्वयं प्रभा के डीटीएच टीवी चैनलों, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट को एकीकृत कर 'एक कक्षा, एक चैनल' की अवधारणा प्रस्तुत की, ताकि जिन परिवारों के पास इंटरनेट नहीं है वहाँ भी टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से शिक्षा पहुँच सके।

उच्च शिक्षा में 'स्वय' (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) मंच पर विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनके क्रेडिट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अंतर्गत मान्यता दी जा सकती है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ई–पीजी पाठशाला तथा विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम चलाने की अनुमति ने ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में 'स्किल इंडिया डिजिटल' जैसे मंच व्यावसायिक प्रशिक्षण को ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। राजस्थान राज्य ने भी इन राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप कदम उठाए। महामारी के दौरान 'स्माइल' (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट) कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों के व्हाट्सऐप समूहों में प्रतिदिन अध्ययन सामग्री भेजी गई, जबकि 'ई–कक्षा' के माध्यम से कक्षावार वीडियो पाठ उपलब्ध कराए गए। दूरदर्शन पर 'शिक्षा दर्शन' और आकाशवाणी पर 'शिक्षावाणी' जैसे कार्यक्रमों ने उन विद्यार्थियों तक पहुँचने का प्रयास किया जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था। इस प्रकार नीति का उद्देश्य बहु–माध्यम रणनीति के द्वारा अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुँचना रहा है।

नीतिगत दृष्टि से देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा नीति के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं: पहुँच (एक्सेस) का विस्तार, शिक्षा की लागत में कमी और सीखने में लचीलापन। ये तीनों लक्ष्य सीधे ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं से जुड़े हैं, क्योंकि दूरी, आर्थिक बोझ और समय की कमी ही उनकी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधाएँ रही हैं।

सीकर जिले की शैक्षिक पृष्ठभूमि

सीकर जिला राजस्थान के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या लगभग 26.8 लाख थी, जिसमें से लगभग तीन–चौथाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। जिले की कुल साक्षरता दर लगभग 72 प्रतिशत थी, किंतु पुरुष साक्षरता (लगभग 85 प्रतिशत) और महिला साक्षरता (लगभग 58 प्रतिशत) के बीच लगभग 27 प्रतिशत अंकों का बड़ा अंतर था। यह अंतर दर्शाता है कि ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा जिले की एक बड़ी चुनौती रही है। शेखावाटी क्षेत्र की एक विशिष्ट सामाजिक विशेषता यहाँ के परिवारों का सेना, सरकारी सेवाओं और खाड़ी देशों में रोजगार

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

से जुड़ाव है। इस कारण क्षेत्र में शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रमुख साधन माना जाता है। इसी आकांक्षा ने सीकर शहर को पिछले दो दशकों में नीट और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का बड़ा केंद्र बना दिया है। जिले के गाँवों से बड़ी संख्या में युवा शहर में किराए के कमरों और छात्रावासों में रहकर तैयारी करते हैं।

परंतु यह अवसर सभी ग्रामीण युवाओं के लिए समान रूप से सुलभ नहीं है। कोचिंग शुल्क, छात्रावास का किराया और भोजन व्यय मिलकर एक साधारण किसान या मजदूर परिवार के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाते हैं। बालिकाओं के मामले में परिवार प्रायः उन्हें घर से दूर भेजने में संकोच करते हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण युवाओं का एक बड़ा वर्ग या तो गाँव के सीमित संसाधनों में पढ़ाई करता है या बीच में ही शिक्षा छोड़ देता है। विद्यालयी शिक्षा की दृष्टि से जिले में सरकारी विद्यालयों का व्यापक नेटवर्क है और राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालय भी आरंभ किए हैं। फिर भी ग्रामीण विद्यालयों में विषय–विशेषज्ञ शिक्षकों, विज्ञान प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर सुविधाओं की कमी की शिकायत बनी रहती है। असर रिपोर्टें यह दर्शाती रही हैं कि ग्रामीण राजस्थान में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी कक्षा के अपेक्षित स्तर से नीचे पढ़ने और गणित करने में सक्षम हैं, और महामारी के दौरान यह अधिगम अंतराल और बढ़ा। डिजिटल पहुँच के संदर्भ में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें दौर ने दिखाया कि ग्रामीण भारत में बहुत कम परिवारों के पास कंप्यूटर था और इंटरनेट सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों का अनुपात शहरी परिवारों की तुलना में बहुत कम था। महामारी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की उपलब्धता तेजी से बढ़ी है, किंतु प्रायः एक ही फोन पूरे परिवार का होता है। यही पृष्ठभूमि सीकर के ग्रामीण युवाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों और सीमाओं, दोनों को निर्धारित करती है।

ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में ऑनलाइन शिक्षा का योगदान

ऑनलाइन शिक्षा नीति ने सीकर जैसे जिले के ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में कई स्तरों पर योगदान दिया है। इसे निम्नलिखित आयामों में समझा जा सकता है।

i. **गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुँचः** पहले गाँव का विद्यार्थी केवल अपने विद्यालय के शिक्षक और उपलब्ध पाठ्यपुस्तक पर निर्भर था। अब दीक्षा, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय और यूट्यूब जैसे मंचों के माध्यम से वह देश के श्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान हिंदी में भी देख सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के बीच ज्ञान–स्रोतों का अंतर कुछ हद तक कम हुआ है।

ii. **प्रतियोगी परीक्षाओं की कम खर्चीली तैयारीः** सीकर के संदर्भ में यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ऑनलाइन कोचिंग, रिकॉर्डेड कक्षाएँ, मॉक टेस्ट और डिजिटल नोट्स के कारण अनेक ग्रामीण युवा शहर में रहे बिना या कम समय रहकर अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग की तुलना में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रायः काफी कम शुल्क पर

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

उपलब्ध होते हैं, जिससे निम्न आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए भी नीट, जेईई, पटवारी, शिक्षक भर्ती, पुलिस और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी संभव हुई है।

iii. **ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण:** जिन बालिकाओं को सामाजिक या सुरक्षा कारणों से उच्च शिक्षा या कोचिंग के लिए शहर नहीं भेजा जाता, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने का साधन बनी है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों के कारण विवाह के बाद भी शिक्षा जारी रखना अपेक्षाकृत आसान हुआ है। यह सीकर जिले में साक्षरता के लैंगिक अंतर को कम करने की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

iv. **उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लचीलापन:** खेती, पशुपालन या पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बँटाने वाले युवा नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते। स्वयं के पाठ्यक्रम और ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण उन्हें अपनी सुविधा के समय पर सीखने का अवसर देते हैं। कंप्यूटर, डिजिटल विपणन, लेखा, भाषा कौशल और कृषि–तकनीक से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम उनके रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएँ बढ़ाते हैं।

v. **डिजिटल साक्षरता और आत्मविश्वास:** ऑनलाइन शिक्षा का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह है कि युवा ऑनलाइन फॉर्म भरने, ई–मेल, डिजिटल भुगतान और सरकारी पोर्टलों के उपयोग में दक्ष हुए हैं। यह डिजिटल साक्षरता उन्हें सूचना तक स्वतंत्र पहुँच और निर्णय लेने की क्षमता देती है, जो सेन और फ्रेरे के अर्थ में सशक्तिकरण का मूल तत्व है।

vi. **महामारी के दौरान शिक्षा की निरंतरता:** विद्यालय बंद रहने के समय 'स्माइल', 'ई–कक्षा' और पीएम ई–विद्या जैसी पहलों ने कम से कम उन विद्यार्थियों की पढ़ाई का क्रम बनाए रखा जिनके परिवार में स्मार्टफोन उपलब्ध था। यद्यपि इसकी पहुँच सार्वभौमिक नहीं थी, फिर भी इसने शिक्षा के पूर्ण विराम को रोकने में भूमिका निभाई।

ऑनलाइन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

ऑनलाइन शिक्षा की संभावनाएँ जितनी व्यापक हैं, सीकर के ग्रामीण संदर्भ में उसकी चुनौतियाँ भी उतनी ही गहरी हैं। प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं।

i. **डिजिटल विभाजन:** ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उसी को मिलता है जिसके पास उपकरण और इंटरनेट हो। अनेक ग्रामीण परिवारों में एक ही स्मार्टफोन होता है, जो दिन में प्रायः परिवार के कमाने वाले सदस्य के पास रहता है। एक से अधिक बच्चों वाले परिवारों में पढ़ाई के लिए फोन का बँटवारा कठिन हो जाता है। लैपटॉप या कंप्यूटर तो बहुत कम परिवारों के पास है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अध्ययन ने भी पाया कि महामारी के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों के बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँच ही नहीं पाए।

ii. **नेटवर्क और बिजली की समस्या:** जिले के दूरस्थ गाँवों और ढाणियों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है। वीडियो व्याख्यान बार–बार रुकते हैं और डेटा का खर्च भी गरीब

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

परिवारों पर भार बनता है। बिजली कटौती के कारण फोन चार्ज करना भी एक समस्या बन जाती है।

iii. **लैंगिक डिजिटल अंतर:** परिवार में फोन पर पहला अधिकार प्रायः बेटों का माना जाता है। बालिकाओं के फोन उपयोग पर सामाजिक निगरानी और प्रतिबंध अधिक होते हैं। इस कारण जो ऑनलाइन शिक्षा बालिकाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकती थी, वही कई बार उनके लिए सबसे कम सुलभ रह जाती है।

iv. **अधिगम की गुणवत्ता और संवाद का अभाव:** ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संवाद सीमित होता है। छोटी कक्षाओं के बच्चों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को स्वयं–अध्ययन में कठिनाई होती है, क्योंकि घर पर उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता। व्हाट्सऐप पर भेजी गई सामग्री को केवल प्राप्त कर लेना और उसे वास्तव में समझ लेना दो अलग बातें हैं।

v. **शिक्षकों की डिजिटल क्षमता:** ग्रामीण विद्यालयों के अनेक शिक्षक डिजिटल शिक्षण विधियों में पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं हैं। ऑनलाइन कक्षा को रोचक और सहभागी बनाना, ऑनलाइन मूल्यांकन करना और विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखना उनके लिए नई चुनौतियाँ हैं।

vi. **भाषा और विषयवस्तु की प्रासंगिकता:** उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अधिकांश गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन सामग्री अंग्रेजी में है। हिंदी में सामग्री बढ़ी है, परंतु स्थानीय बोली और ग्रामीण जीवन से जुड़े उदाहरणों वाली सामग्री अब भी कम है।

vii. **स्क्रीन समय और मानसिक दबाव:** लंबे समय तक मोबाइल पर पढ़ाई से आँखों पर दबाव, ध्यान भटकना और सोशल मीडिया की लत जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में अकेलेपन और तनाव की समस्या भी देखी गई है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में साथियों और शिक्षकों का भावनात्मक सहारा कम मिलता है।

ऑनलाइन शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

सीकर जिले के ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।

i. **डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:** भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक पहुँचे ब्रॉडबैंड को विद्यालयों, पुस्तकालयों और सामुदायिक भवनों तक विस्तारित किया जाए। दूरस्थ ढाणियों में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाई जाए और विद्यालयों में सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग की व्यवस्था की जाए।

ii. **सामुदायिक डिजिटल अध्ययन केंद्र:** प्रत्येक ग्राम पंचायत या बड़े गाँव में ई–मित्र केंद्रों, सरकारी विद्यालयों अथवा पंचायत भवनों में निःशुल्क वाई–फाई, कंप्यूटर और शांत अध्ययन स्थल वाले डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएँ। ये केंद्र विशेष रूप से उन

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

युवाओं और बालिकाओं के लिए उपयोगी होंगे जिनके घर में उपकरण या पढ़ाई का वातावरण नहीं है।

iii. **उपकरण और डेटा सहायता:** मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन तथा रियायती डेटा पैक उपलब्ध कराने की योजनाओं का विस्तार किया जाए। इसमें बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि लैंगिक डिजिटल अंतर कम हो सके।

iv. **मिश्रित शिक्षण मॉडल:** ऑनलाइन शिक्षा को कक्षा–शिक्षण का विकल्प न मानकर उसका पूरक बनाया जाए। विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से डिजिटल सामग्री का उपयोग हो और सप्ताह में निश्चित समय पर शिक्षक विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करें।

v. **शिक्षक प्रशिक्षण:** ग्रामीण शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षण विधियों, ऑनलाइन मूल्यांकन और सामग्री निर्माण पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। दीक्षा मंच पर उपलब्ध शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से उन्हें जोड़ा जाए।

vi. **स्थानीय भाषा में सामग्री:** हिंदी और स्थानीय संदर्भ वाली गुणवत्तापूर्ण ई–सामग्री का निर्माण किया जाए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीकर स्थानीय शिक्षकों की सहायता से राज्य पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो और अभ्यास सामग्री तैयार कर सकता है।

vii. **निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन:** राज्य सरकार की कोचिंग सहायता योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़कर ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क या रियायती ऑनलाइन कोचिंग, मॉक टेस्ट और करियर परामर्श उपलब्ध कराया जाए।

viii. **अभिभावक और समुदाय की भागीदारी:** पंचायतों, विद्यालय प्रबंधन समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अभिभावकों में बालिकाओं की ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए तथा सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की जानकारी दी जाए।

ix. **डिजिटल कल्याण और परामर्श:** विद्यार्थियों को स्क्रीन समय के संतुलित उपयोग, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श सेवाएँ उपलब्ध हों।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन शिक्षा नीति ने सीकर जिले के ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएँ खोली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पीएम ई–विद्या, दीक्षा, स्वयं और राजस्थान सरकार की 'स्माइल' व 'ई–कक्षा' जैसी पहलों ने गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री को गाँव तक पहुँचाया है। शिक्षा के प्रति गहरी आकांक्षा वाले सीकर जिले में ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल संसाधनों ने उन युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर दिया है जो शहर में रहकर महँगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते थे। ग्रामीण बालिकाओं के लिए घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने की संभावना इस नीति का सबसे सकारात्मक पक्ष है। फिर भी अध्ययन यह भी दर्शाता है कि

ऑनलाइन शिक्षा स्वयं में सशक्तिकरण की गारंटी नहीं है। डिजिटल विभाजन, कमजोर नेटवर्क, उपकरणों की कमी, लैंगिक असमानता, शिक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष संवाद के अभाव के कारण इसका लाभ समान रूप से नहीं पहुँच पाता। यदि इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो ऑनलाइन शिक्षा उन्हीं युवाओं को आगे बढ़ाएगी जो पहले से संसाधन–संपन्न हैं, और वंचित वर्ग और पीछे छूट सकता है। अतः ऑनलाइन शिक्षा नीति को ग्रामीण संदर्भ में सफल बनाने के लिए डिजिटल अवसंरचना, सामुदायिक डिजिटल अध्ययन केंद्र, उपकरण सहायता, स्थानीय भाषा में सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण और मिश्रित शिक्षण मॉडल पर समन्वित रूप से कार्य करना आवश्यक है। जब तकनीक के साथ मानवीय मार्गदर्शन, सामाजिक जागरूकता और समान अवसर जुड़ेंगे, तभी ऑनलाइन शिक्षा सीकर के ग्रामीण युवाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सम्पन्न कर वास्तविक अर्थों में सशक्त बना सकेगी। भविष्य के शोध में जिले के विभिन्न तहसीलों के ग्रामीण युवाओं पर प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के वास्तविक प्रभाव का मात्रात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची:

1. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय. (2020). ऑनलाइन शिक्षा के मिथक. शिक्षा में क्षेत्रीय अध्ययन. बेंगलुरुः अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय.
2. भारत की जनगणना. (2011). जिला जनगणना पुस्तिकाः सीकर, राजस्थान. नई दिल्लीः जनगणना संचालन निदेशालय, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय.
3. ढवन, एस. (2020). ऑनलाइन अधिगमः कोविड–19 संकट के समय में रामबाण. जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, 49(1), 5–22.
4. फ्रेरे, पी. (1970). उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र. न्यूयॉर्कः हर्डर एंड हर्डर.
5. जेना, पी. के. (2020). भारत में शिक्षा पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च, 12(7), 12582–12586.
6. शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्लीः भारत सरकार.
7. शिक्षा मंत्रालय. (2020). पीएम ई–विद्याः डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा तक बहु–माध्यम पहुँच (प्रेस विज्ञप्ति). नई दिल्लीः भारत सरकार.
8. शिक्षा मंत्रालय. (2022). शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यू–डाइस प्लस) 2021–22. नई दिल्लीः भारत सरकार.
9. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. (2020). भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोगः एनएसएस 75वाँ दौर (जुलाई 2017–जून 2018), रिपोर्ट संख्या 585. नई दिल्लीः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय.
10. प्रथम. (2021). शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021. नई दिल्लीः असर केंद्र.
11. प्रथम. (2023). शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2022. नई दिल्लीः असर केंद्र.

12. सेन, ए. (1999). विकासः स्वतंत्रता के रूप में. न्यूयॉर्कः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
13. यूनेस्को. (2020). वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020ः समावेशन और शिक्षा – सभी का अर्थ है सभी. पेरिसः यूनेस्को.
14. यूनेस्को. (2023). वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023ः शिक्षा में प्रौद्योगिकी – किसकी शर्तों पर एक साधन? पेरिसः यूनेस्को.
15. कबीर, एन. (1999). संसाधन, कर्तृत्व, उपलब्धियाँः महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार. डेवलपमेंट एंड चेंज, 30(3), 435–464.